



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷிண் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினகரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित



5 कुलदीप यादव एकदिवसीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसके

6 संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का ऐसा अपमान किसे स्वीकार्य होगा?

7 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का हिस्सा होंगे बाँबी देओल

फर्स्ट टेक

दीपावली-छठ के मौके पर बिहार के लिए 12000 ट्रेन सेवायें

नई दिल्ली/भाषा। रेलवे दीपावली और छठ के अवसर पर बिहार के लिए 12000 से अधिक ट्रेन सेवायें संचालित करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यहां बताया कि दीपावली और छठ के मौके पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने इस दौरान 12000 से अधिक ट्रेन सेवायें संचालित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुधाकर चौधरी, सांसद संजय झा और सांसद डॉ. संजय जायसवाल की मौजूदगी में यह घोषणा की। बिहार के इन नेताओं ने रेल भवन में वैष्णव से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि गया से दिल्ली के लिए नई अमृत भारत ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

स्टारलिक ग्राहकों के सत्यापन के लिए करेगी 'आधार' का इस्तेमाल

नई दिल्ली/भाषा। अरबपति एलन मस्क की अगुवाई वाली स्टारलिक भारत में ग्राहकों को जोड़ने से पहले उनके सत्यापन के लिए 'आधार' प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करेगी। बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं देने वाली इकाई स्टारलिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। स्टारलिक ग्राहकों के सत्यापन के लिए 'आधार' प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करेगी। स्टारलिक के ग्राहक जोड़ने के पहले आधार का इस्तेमाल करने से पूरी प्रक्रिया सुचारु, सुरक्षित और बहुत आसान हो जाएगी। यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भुवनेश कुमार और स्टारलिक इंडिया के निदेशक पर्नील उध्वरेशे की मौजूदगी में इस साझेदारी पर सहमति जताई गई।

बांग्लादेश में आम चुनाव अगले साल फरवरी में

ढाका/भाषा। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में 13वें संसदीय चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के इस बाबत इसी सप्ताह एक ब्यौरेवार कार्ययोजना जारी किए जाने की संभावना है। चुनाव आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने सरकारी संस्था बांग्लादेश संग्रहालय संस्था (बीएसएस) को बताया कि चुनाव रोडमैप का एक मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना चुनावों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय और संचालन संबंधी मुद्दों पर केंद्रित होगी।

21-08-2025 सुबोत 6:26 बजे 22-08-2025 सुबोत 5:57 बजे

BSE 81,857.84 (+213.45) NSE 25,050.55 (+69.90)

सोना 10,418 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम चांदी 127,000 रु. प्रति किलो

मिशान मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी पत्रिका
epaper.dakshinbharat.com



केलाशा मण्डेला, मो. 9828233434

आओ सोचें नया

छोड़ें बीते कल की बातें, हम लिखें नया इतिहास आज। सबसे पहले हो राष्ट्रधर्म, हों जाति मुक्त सारे समाज। हो राजनीति भी दल विहीन, गुणियाँ-सच्चों को मिले राज। हर मन में हो सौहार्दभाव, हर योग्य व्यक्ति को मिले काज।।

देश की जनता तय करेगी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चलाएंगे या नहीं : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि अब देश की जनता को यह तय करना होगा कि क्या जेल में रहकर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सरकार चलाना उचित है। इससे पहले, गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए गए और लगातार 30 दिन हिरासत में रखे गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के प्रावधान वाले तीन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किए गए, जिन्हें सदन ने अध्ययन के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने का फैसला किया।

शाह ने विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में 'संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025' और 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025'

■ गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए गए और लगातार 30 दिन हिरासत में रखे गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के प्रावधान वाले तीन विधेयक लोकसभा में पेश, संसद की संयुक्त समिति को भेजने का फैसला



पेश किए। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया।

शाह ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने आप को कानून के दायरे में लाने का संविधान संशोधन पेश किया है और दूसरी ओर 'कानून के दायरे से बाहर रहने, जेल से सरकारें चलाने एवं कुर्सी का मोह

मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के आक्रोश को देखकर उन्होंने संसद में लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया, ताकि महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री जेल में रहते हुए सरकार न चला पाएं। उन्होंने लिखा, इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना और राजनीति में शुचिता लाना है। शाह ने कहा कि इन तीनों विधेयक से जो कानून अस्तित्व में आएगा, वह यह है कि: कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुआ हमला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय मुख्यमंत्री गुप्ता आम लोगों की शिकायतें सुन रही थीं। एक शख्स भी अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा और उसने श्रीमती गुप्ता पर हमला कर दिया। उसके इस हमले की वजह



का फिलहाल पता नहीं चला है। पुलिस हमलावर शख्स को हिरासत में लेकर पृच्छाछ कर रही है।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है।

इजराइल की गाजा में युद्ध के नए चरण की योजना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

यरूशलम/एपी। इजराइल आने वाले दिनों में गाजा शहर में एक व्यापक सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी में जुटा है। वहीं दूसरी ओर वार्ताकार इजराइल और हमास के बीच 22 महीनों से जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए युद्धविराम की कोशिशों में लगे हुए हैं।

इजराइली सेना ने बुधवार को बताया कि रक्षा मंत्री ने गाजा के कुछ सबसे घनी आबादी वाले



इलाकों में अभियान के एक नए चरण की शुरुआत की योजना को मंजूरी दे दी है।

सेना के मुताबिक, 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा और वर्तमान में सेवारत अतिरिक्त 20,000

जीएसटी सुधार आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग, छोटे कारोबारियों के फायदे के लिए : सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जीएसटी सुधारों के माध्यम से आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों के फायदे के लिए : सीतारमण

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही इसके माध्यम से

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को और सरलीकृत, पारदर्शी और विकासोन्मुखी करने का प्रयास है।

उन्होंने जीएसटी परिषद द्वारा क्षतिपूर्ति उपकर, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, तथा दरों के युक्तिकरण पर गठित मंत्रिसमूहों (जीओएम) को संबोधित करते हुये यह बात कही।

बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री, बिहार के

उपमुख्यमंत्री और तीनों जीओएम में शामिल राज्यों के वित्त मंत्री भी उपस्थित थे।

केंद्र सरकार सहकारी संघवाद की भावना के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लागू करने के लिए आने वाले हफ्तों में राज्यों के साथ व्यापक सहमति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

दो दिन की इस बैठक में मंत्रियों के नेतृत्व में जीएसटी दरों के

भारत-रूस संबंधों पर जयशंकर

अधिक कार्य करना और अलग ढंग से कार्य करना हमारा मंत्र होना चाहिए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत और रूस को कहा कि भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए रचनात्मक और अभिनव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जयशंकर ने यह बात ऐसे में कही जब रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना करके 50 प्रतिशत करने के अमेरिकी



राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आ गया है। जयशंकर ने यह टिप्पणी मॉस्को में रूस के प्रथम उप-प्रधानमंत्री

विविधता लाकर और अधिक संयुक्त उद्यमों के माध्यम से अपने सहयोग के "एजेंडे" में निरंतर विविधता लानी चाहिए और उसका विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा, "अधिक काम करना और अलग तरीके से काम करना हमारा मंत्र होना चाहिए।" जयशंकर ने मंगलवार को रूस की तीन दिवसीय यात्रा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत-रूस की "समय की कसौटी पर खरी उतरते" साझेदारी को और मजबूत करना है।

नासा ने यूरेनस की कक्षा में एक नया लघु चंद्रमा खोजा

न्यूयॉर्क/एपी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि उसके वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सौरमंडल के सातवें ग्रह यूरेनस की कक्षा में एक नया, अत्यंत छोटा चंद्रमा खोजा है। नासा श्रेरा मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, यह चंद्रमा लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा प्रतीत होता है और इसे इसी वर्ष फरवरी में वेब टेलीस्कोप के 'नियर इन्फ्रारेड कैमरे' के माध्यम से देखा गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चंद्रमा अपनी अत्यंत क्षीण चमक और छोटे आकार के कारण अब तक छिपा रहा, यहां तक कि लगभग 40 वर्ष पहले यूरेनस के समीप से गुज़रेंगे यॉर्गेज-2 अंतरिक्ष यान की निगाहों से भी यह बचा रहा। यूरेनस के अब तक 28 ज्ञात चंद्रमा हैं।

रूस को सुदर्शन चक्र परियोजना का हिस्सा बनने की उम्मीद : रूस

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुशकिन ने बुधवार को कहा कि रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत के खिलाफ अमेरिका की दंडात्मक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए रूस के पास एक "विशेष तंत्र" है।

भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना करके 50 प्रतिशत करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण हुए हैं। बाबुशकिन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नयी दिल्ली के साथ अपने देश के संबंधों में

तेजी से सुधार होने की उम्मीद जताई और कहा कि विभिन्न सैन्य साजोसामान व उपकरण की आवश्यकता के लिए भारत का "संसदीया साझेदार" रहा है।

वरिष्ठ रूसी राजनयिक ने कहा कि नयी दिल्ली की सुदर्शन चक्र नामक एक नयी वायु रक्षा प्रणाली बनाने की योजना का रूस के हिस्सा होने की उम्मीद है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान की थी। उन्होंने कहा, "हम इस समझ से आगे बढ़ रहे हैं कि जब इन प्रणालियों को आगे बढ़ाने की बात आएगी, तो रूसी उपकरण इसका हिस्सा होंगे।"

हमला सिर्फ मुझ पर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा करने के हमारे संकल्प पर हुआ : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान उन पर हुआ हमला लोगों की सेवा करने के उनके संकल्प को डिगाने का एक "कायरतापूर्ण प्रयास" है, लेकिन इससे उनका मनोबल नहीं टूटा है।

बुधवार सुबह गुप्ता के कैप कार्यालय में 'जन सुनवाई' के दौरान उन पर हमला किया गया। हमले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि जन सुनवाई कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प को डिगाने के लिए किया गया एक कायराना प्रयास है।

उन्होंने कहा, स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी।

गुप्ता ने कहा, ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके साथ आगे बढ़ें, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

शुल्क अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय बैंक को सतर्क रहने की जरूरत: मल्होत्रा ने एमपीसी बैठक में कहा



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि शुल्क को लेकर अनिश्चितताएं अभी भी जारी हैं, इसलिए केंद्रीय बैंक को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने इस महीने के शुरू में मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर को यथावत रखने के पक्ष में मतदान करते हुए यह बात कही थी।

आरबीआई ने बुधवार को चार-छह अगस्त के दौरान हुई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक का ब्योरा जारी किया। केंद्रीय बैंक के गवर्नर के साथ एमपीसी के

हरियाणा सरकार ने वन की परिभाषा अधिसूचित की

चंडीगढ़/भाषा। हरियाणा सरकार ने वन के "शब्दकोशीय अर्थ" को परिभाषित किया है, तथा वन विशेषज्ञ ने चिंता व्यक्त की है कि इस परिभाषा से अरावली के संभावित वन का ज्यादातर भाग वन संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर हो जायेगा। हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग ने वन की परिभाषा अधिसूचित कर दी है।

राज्य सरकार ने 18 अगस्त की अधिसूचना में "वन शब्द को शब्दकोष के अर्थ के अनुसार परिभाषित किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि भूमि का कोई टुकड़ा "शब्दकोश अर्थ के अनुसार वन" माना जाएगा, बशर्ते यह कुछ शर्तें पूरी करता हो। अधिसूचना में कहा गया है कि परिभाषा के अनुसार वन क्षेत्रों में न्यूनतम आच्छादित घनत्व 40 प्रतिशत होना चाहिए तथा पृथक होने पर कम से कम पांच हेक्टेयर

क्षेत्र में फैला होना चाहिए, या सरकार श्रेता अधिसूचित वनों से सटे होने पर दो हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होना चाहिए।

आच्छादित घनत्व का मतलब है किसी जंगल या वन क्षेत्र में पेड़ों के पत्तों और टहनियों से ढके हुए क्षेत्र का अनुपात। हालांकि सरकार श्रेता अधिसूचित वनों के बाहर स्थित सभी रेंजिक / कॉम्पैक्ट / कृषि-वानिकी वृक्षारोपण और बागों को इस परिभाषा के अंतर्गत वन नहीं माना जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है, भूमि का एक टुकड़ा "शब्दकोश अर्थ के अनुसार वन" माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है: यदि यह अलग-थलग है और इसका न्यूनतम क्षेत्रफल पांच हेक्टेयर है; तथा यदि यह सरकार श्रेता अधिसूचित वनों के समीप है तो इसका न्यूनतम क्षेत्रफल दो हेक्टेयर है।

महाराष्ट्र में बारिश की स्थिति नियंत्रण में : फडणवीस बांधों से पानी छोड़ने को लेकर अन्य राज्यों से समन्वय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पुणे/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि भारी बारिश से बेहाल मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी में एक दिन

पहले हुई मूसलाधार बारिश से अब राहत मिली है।

फडणवीस ने कहा कि राज्य में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के जवानों को तैनात करके आपदा प्रबंधन के संबंध में सभी आवश्यक



सावधानियां बरती जा रही हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, बांधों से पानी छोड़े जाने का प्रबंधन किया जा रहा है। सरकार हमारे अनुरोध के अनुसार पानी छोड़े जाने के अनुरोध को शीघ्र तार्किक पक्षों से ढके हुए क्षेत्र का अनुपात। हालांकि सरकार श्रेता अधिसूचित वनों के बाहर स्थित सभी रेंजिक / कॉम्पैक्ट / कृषि-वानिकी वृक्षारोपण और बागों को इस परिभाषा के अंतर्गत वन नहीं माना जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है, भूमि का एक टुकड़ा "शब्दकोश अर्थ के अनुसार वन" माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है: यदि यह अलग-थलग है और इसका न्यूनतम क्षेत्रफल पांच हेक्टेयर है; तथा यदि यह सरकार श्रेता अधिसूचित वनों के समीप है तो इसका न्यूनतम क्षेत्रफल दो हेक्टेयर है।

पंजाब : ईडी ने 'मुआफी जमीन' मामले में छापेमारी की

जालंधर/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'मुआफी जमीन' का कुछ संस्थाओं श्रेता कथित तौर पर दुरुपयोग किए जाने से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत पंजाब और चंडीगढ़ में अकाली दल के एक नेता के ठिकानों समेत विभिन्न परिसरों पर बुधवार को छापेमारी की।

सूत्रों ने बताया कि वाहिद संधार शुगर लिमिटेड और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कम से कम आठ स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं।

अस्त-व्यस्त हो गया था। निचले इलाके जलमग्न होने की वजह से उपनगरीय रेल सेवाएं बाधित हो गई थीं। मुख्यमंत्री ने कहा, मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बारिश की स्थिति कुल मिलाकर काफी हद तक नियंत्रण में है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में अब भी भारी बारिश हो रही है। फडणवीस ने दोहराया कि 14 लाख हेक्टेयर में फसलें नष्ट हो गई हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिमला/भाषा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और ऊना, कुल्लू और मंडी जिलों के कुछ इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़े हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ऊना के अंब और गगरेट अनुमंडलों में एहतियात के तौर पर शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। कुल्लू के मनाली और बंजार व मंडी जिले के इलाकों में अचानक आई बाढ़, बाढ़ल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के बाद इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं।

कुल्लू के शास्त्री नगर में नाले में अचानक आई बाढ़ से घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।



हालांकि, कुल्लू नगर परिषद के अध्यक्ष महंत गोपाल दास ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट श्रेता जारी एक बयान में कहा गया कि सोमवार रात बाढ़ल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ की वजह से मंडी जिले के सिलगुधानी गांव में एक पैदल पुल बह गया। बयान में

भारत, यूरेशियन आर्थिक संघ ने व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए किया समझौता

नई दिल्ली/भाषा। भारत और पांच देशों के यूरेशियन आर्थिक संघ (ईईयू) ने बुधवार को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए नियम एवं शर्तों पर हस्ताक्षर किए। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। यूरेशियन आर्थिक संघ (ईईयू) के पांच सदस्य आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस हैं। यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अमेरिका श्रेता के डॉलर प्रति किलोग्राम तक लाया जा सका, तो वह ऊर्जा आयातक से वैश्विक निर्यातक बन सकता है।

द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टिट्यूट में आयोजित 24वें दक्षिण सेंट स्मूथ व्याख्यान में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में हाइड्रोजन की लागत लगभग पांच से छह डॉलर प्रति किलोग्राम है, जो पारंपरिक ईंधनों की तुलना में काफी महंगी है। गडकरी ने कहा, यदि हम इसे एक डॉलर प्रति किलोग्राम तक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि यदि देश में हाइड्रोजन बनाने की लागत को एक डॉलर प्रति किलोग्राम तक लाया जा सका, तो वह ऊर्जा आयातक से वैश्विक निर्यातक बन सकता है।

द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टिट्यूट में आयोजित 24वें दक्षिण सेंट स्मूथ व्याख्यान में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में हाइड्रोजन की लागत लगभग पांच से छह डॉलर प्रति किलोग्राम है, जो पारंपरिक ईंधनों की तुलना में काफी महंगी है। गडकरी ने कहा, यदि हम इसे एक डॉलर प्रति किलोग्राम तक



लाने में सफल हो जाते हैं, तो भारत मौजूदा तेल उत्पादक देशों के समान स्थिति में पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन, ऊर्जा के भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी बाधा हाइड्रोजन 'फिलिंग स्टेशन' स्थापित करने और ईंधन के परिवहन के लिए प्रणालियां विकसित करने में है। उन्होंने कहा, इन क्षेत्रों में तत्काल और व्यापक स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। ऊर्जा के लिए कचरे के उपयोग की संभावना के बारे में गडकरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। संसद ने गुवाहाटी में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) की स्थापना के प्रावधान वाले एक विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ रुपए के आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है तथा संस्थान में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही दाखिला शुरू हो जाएगा।

राज्यसभा ने आज भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा एवं शिक्षा मंत्री के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे मंगलवार को ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर चर्चा एवं पारित किए

लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक की प्रतियां फाड़ी गईं, कागज उछाले गए



फेंके। इस दौरान गृह मंत्री विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश कर रहे थे। इसी हंगामे में, तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी को शाह के सामने लगे माइक्रोफोन को खींचते हुए और उसके पास नारे लगाने की कोशिश करते देखा गया।

उधर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद भी आसन के सामने मौजूद विपक्षी सांसदों की

को फाड़ दिया और कागज के टुकड़े उछालने लगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस हंगामे के बीच कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तीन मार्शलों को गृह मंत्री के आसन के सामने खड़े होना पड़ा।

तीन बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले, तीन महिलाओं सहित संसदीय सुरक्षा सेवा के 12 सदस्य सत्ता पक्ष की सीटों के बगल वाले गलियारे में खड़े देखे गए, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया।

जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों को सत्ता पक्ष की सीटों के पास आने से रोकने के लिए मार्शल आसन के पास पहुंच गए, लेकिन जल्द ही उन्हें वापस बुला लिया गया।

लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के इस आचरण की कड़ी निंदा की और कहा कि उनके कार्यों ने लोकसभा की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है।

सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही शाह सदन में आए और अपनी सामान्य अग्रिम पंक्ति की सीट की बजाय पिछली पंक्ति में बैठ गए। उन्होंने तीनों विधेयकों को गहन परीक्षण के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने पारित कर दिया।

हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही शाम 5:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।



एलायंस एयर का विमान तकनीकी खामी के कारण बीच रास्ते से गुवाहाटी हवाई अड्डे पर लौटा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोदोलोई अंतरराष्ट्रीय (एजीबीआई) हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए रवाना हुई एलायंस एयर की उड़ान बुधवार को तकनीकी खामी की वजह से 'पूर्ण आपात स्थिति' में वापस लौट आई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

हवाई अड्डे की प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं, और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया, तकनीकी खराबी के कारण

गुवाहाटी-कोलकाता उड़ान को वापस उतारने का फैसला किए जाने के बाद, 20 अगस्त को अपराह्न 1.42 बजे गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। हवाईअड्डा सूत्र ने बताया कि विमान ने अपराह्न 1.09 बजे गुवाहाटी से कोलकाता के लिए उड़ान भरी थी। प्रवक्ता ने बताया कि विमान अपराह्न 2.27 बजे सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे पर उतर गया और अपराह्न 2.40 बजे आपात स्थिति की घोषणा वापस ले ली गई। बयान में दावा किया गया कि इस घटना के कारण हवाई अड्डे के परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

जैन समुदाय को पर्यषण पर्व संबंधी याचिका पर उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत

मुंबई/भाषा। मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को जैन समुदाय के सदस्यों को उनके पर्यषण पर्व के दौरान शहर में 10 दिनों के लिए बूचड़खानों को बंद करने के अनुरोध पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश आलोक अरोरा और न्यायमूर्ति संदीप मांन की पीठ ने कहा कि यह समुदाय की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन संवალ यह है कि उसे (समुदाय को) बूचड़खानों को 10 दिनों तक बंद रखने की मांग करने का अधिकार कहां (किस वैधानिक प्रावधान) से मिलता है। याचिकाओं में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त श्रेता 14 अगस्त को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बूचड़खानों को केवल दो दिनों के लिए बंद करने की अनुमति दी गई थी। आयुक्त ने तर्क दिया था कि शहर में जैन समुदाय की आबादी कम है। जैन धर्म की दिगंबर शाखा 20 से 27 अगस्त तक और श्वेतांबर शाखा 21 से 28 अगस्त तक पर्यषण पर्व मनायेगी। उच्च न्यायालय ने कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं श्रेता कोई ठोस दलील नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय ने पृष्ठ, हम आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं है। लेकिन हमें बताइए कि आपको बूचड़खानों को 10 दिनों के लिए बंद करने का अधिकार कहां (किसी वैधानिक प्रावधान) से मिलता है। बीएमसी ने अदालत को बताया कि वर्तमान में सरकार ने वर्ष में 16 दिन बूचड़खानों को बंद रखने की अधिसूचना जारी की है।

संसद ने दी आईआईएम संशोधन विधेयक को मंजूरी, गुवाहाटी में बनेगा प्रबंध संस्थान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जाने के दौरान कई विपक्षी दलों के सदस्य अनुपस्थित थे। विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में सदन से वाकआउट किया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधान ने कहा कि देश में अभी 21 आईआईएम संचालित हो रहे हैं और गुवाहाटी 22वां ऐसा संस्थान होगा। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह देश में 9वां नया आईआईएम होगा। उन्होंने कहा कि 1961 से आईआईएम कार्यरत हैं। 1961 से 2014 तक 53 साल में केवल 13 आईआईएम ही स्थापित हो सकीं। उन्होंने कहा कि 2013-14 में सभी 13 आईआईएम में छात्रों की संख्या 3,500 थी जो 2024-25 में बढ़कर 9,800 हो

गई है। उन्होंने कहा कि यह नए संस्थान बनाने और देश में छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करने के प्रति मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधान ने कहा कि 2017 तक आईआईएम संस्थान डिग्री नहीं दे सकते थे और वे पीजी डिप्लोमा उपाधि प्रदान करते थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2017 में आईआईएम को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, आईआईएम राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बन गए।

प्रधान ने कहा कि संसद श्रेता 2017 में कानून बनाए जाने के बाद आईआईएम पूर्ण विश्वविद्यालय जैसा संस्थान बन गया और जब आईआईएम गुवाहाटी काम करना शुरू करेगा, तो वह विश्वविद्यालय के समान ही

राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2004-14 का समय असम के लिए सबसे खराब था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य की पूरी तरह से अनदेखी की, क्योंकि उनके पास निर्णय लेने की शक्तियां नहीं थीं।

प्रधान ने कहा कि सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने की अनुमति दे रही है आज 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह पिछले दो साल में, अब्बू धाबी और अफ्रीका में दो आईआईएम संस्थान खुले हैं। उन्होंने कहा, आईआईएम हमारे देश का विश्व में एक बड़ा ब्रांड बन गया है। आईआईएम की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा है कि विदेश में भी इसे खोलने की मांग हो रही है।

